बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 218 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 16 जून 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

यात्री से जब्त किया गया सोना लौटाए कस्टम विभाग, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरपोर्ट पर जब्त किए गए सोने को एक यात्री को तत्काल वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि जब्त किया गया सोना वापस करने का आदेश अपील में पहले ही दिया गया था और पुनरीक्षण याचिका में भी निर्णय को सही ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि कस्टम विभाग को संबंधित सोने की चीजें शर्तों को पूरा करने के बाद याचिकाकर्ता को तुरंत वापस कर देनी चाहिए। यह मामला बैंकाक से भारत आ रहे हरीश कुमार के पास मौजूद सोने के गहनों को रोके जाने से जुड़ा था। न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे व न्यायमूर्ति अजय दिगपॉल की पीठ ने कहा कि 27 जून 2025 के एक आदेश के तहत याची को राहत दी जा चुकी है .

17 जून कोटा चलो! राहुल गांधी की अपील- पेपर लीक के खिलाफ़ एकजुट हो युवा, आवाज़ बनो

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं से 17 जून को राजस्थान के कोटा में होने वाले छात्रों की गूंज विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की। विपक्ष के नेता ने सरकार पर आरोप लगाया कि बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने, परीक्षाएं रद्द होने और भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण सरकार भारत के युवाओं को निराश करने में विफल रही है। गांधी ने द्व पर कहा कि आज के भारत में युवाओं को सपने देखने की हिम्मत करने के लिए सज़ा दी जा रही है और कड़ी मेहनत से अब सफलता की गारंटी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हर पेपर लीक, रद्द हुई परीक्षा और रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया एक सिस्टम की विफलता है और यह लाखों छात्रों और नौकरी चाहने वालों के सपनों पर एक चोट है। युवाओं में निराशा और गुस्से को समझते हुए गांधी ने कहा कि जब सरकार सुनने से इनकार कर दे, तो लोगों को अपनी आवाज़ और ज़ोर से उठानी चाहिए। उन्होंने छात्रों से कोटा में एकजुट होने और अपनी चिंताओं को ऐसा बनाने के लिए कहा जिन्हें नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन हो। गांधी ने इस अभियान को भारत के युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताते हुए कहा कि आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दहाड़ बनें जिसे नज़रअंदाज़ न किया जा सके। कोटा से शुरू होकर, यह देश के हर कोने तक पहुँचे। कांग्रेस ने परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक और सरकारी भर्ती में देरी जैसे मुद्दों को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है और छात्रों तथा नौकरी के उम्मीदवारों से जुड़ी चिंताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। गांधी ने कहा कि वे निष्पक्ष अवसरों और रोज़गार के लिए छात्रों के संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। 17 जून का कार्यक्रम कोटा के दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच पर आयोजित किया जाएगा। यह शिक्षा बचाओ, अपना भविष्य बचाओ अभियान के तहत देशव्यापी आउटरीच कार्यक्रम का पहला पड़ाव होगा। इस अभियान के तहत आगे 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। यह सब कॉकरोच जनता पार्टी के देशव्यापी अभियान के बीच हो रहा है। यह एक व्यंग्यात्मक संगठन है जो पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन कर रहा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग कर रहा है। यह मांग परीक्षा में कथित गड़बड़ियों द्व जैसे नीट पेपर लीक और सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी समस्याओं - को लेकर की जा रही है।

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, नोएडा में तेज आंधी, दिन में ही छाया अंधेरा

नई दिल्ली । सोमवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गुरुग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई इलाकों में सुबह-सुबह हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई और उमस भरी गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली। नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में दोपहर में तेज आंधी देखने को मिली। आसमान में काले बादल छा गए। बारिश की बूंदों ने दिन की शुरुआत के साथ ही गर्मी के तेवर को नरम कर दिया। गुरुग्राम-दिल्ली समेत एनसीआर के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस मौसमी बदलाव का सीधा असर दिन के तापमान पर देखने को मिला, जो सामान्य से कुछ डिग्री नीचे चला गया। लोगों ने इस सुहावने मौसम का आनंद लिया और कई जगहों पर लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इस बदलाव का अनुभव करते नजर आए। राजधानी में रविवार को गर्मी के कारण लोग बेहाल दिखे। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। अगले एक सप्ताह तक कड़ी धूप निकलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 20 जून तक अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। रविवार सुबह से पहले न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 4.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, यह अभी भी सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। दोपहर में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 24 घंटों में 2.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार दोपहर से शाम तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूल भरी आंधी चलने और कहीं-कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया था।

यह नया व्यवसाय बन गया है - आरटीआई एक्टिविम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सक्रियता को एक नया व्यवसाय करार देते हुए एक आरटीआई कार्यकर्ता और सड़क निर्माण कार्य में सरकारी कर्मचारी को बाधा पहुंचाने के आरोपी अन्य लोगों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश कुमार बहल और उनके सहयोगी को जमानत देने से इनकार कर दिया और सड़क निर्माण के काम की निगरानी करने के उनके अधिकार पर भी सवाल उठाए। जस्टिस मेहता ने कहा, आरटीआई सक्रियता लोगों के बीच एक नया व्यवसाय बन गया है। केंद्र सरकार ने फंड जारी किया है, वही सड़क निर्माण का ध्यान रखेगी। आप कोई नहीं हैं। तथाकथित आईटीआई एक्टिविस्ट! येलो जर्नलिम... याचिका खारिज। जस्टिस मेहता की राय से सहमत होते हुए जस्टिस बिश्नोई ने कहा, इन सभी सड़कों के निर्माण की निगरानी करने वाले आप कौन हैं? क्या आप कोई उच्च अधिकारी हैं या क्या हैं? बहल ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने सड़क निर्माण कार्य में शामिल भ्रष्टाचार को उजागर किया था। एफआईआर के अनुसार, बहल ने एक अन्य आरोपी राजीव कुमार उर्फ मिंटू के साथ मिलकर पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में बाधा डाली और उस शिकायतकर्ता को भी धमकाया जिसकी देखरेख में काम हो रहा था और साइट पर मौजूद मजदूरों को भी डराया-धमकाया। उन्होंने मजदूर के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और शिकायतकर्ता को चोट भी पहुंचाई। उनके खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 304(2), 132, 221, 121(1), 351(2), 351(3) (बीएनएस 2023 की धारा 3(5), 121(2) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी । पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 14 मई के अपने आदेश में कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सरकारी काम में बाधा डालने में उनकी विशिष्ट और सीधी संलिप्तता को दर्शाते हैं। मामले की सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली में बिजली बिल पर बड़ा अपडेट, सब्सिडी वाले लाखों उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा पीपीएसी का बोझ

नई दिल्ली ।

दिल्ली के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है. पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज हीं करना पड़ेगा. दिल्ली सरकार का दावा है कि सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इस फैसले का असर बेहद सीमित रहेगा. ऊर्जा मंत्री आशीष सूद के अनुसार दिल्ली के कुल 74 लाख बिजली उपभोक्ताओं में से करीब 43.7 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें या तो पूरी सब्सिडी मिल रही है या वे आंशिक सब्सिडी के दायरे में आते हैं. ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल पर पीपीएसी बढ़ोतरी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. सरकार का कहना है कि अतिरिक्त भार केवल उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिनकी मासिक बिजली खपत 400 यूनिट से अधिक है. हालांकि उनके लिए भी यह बढ़ोतरी सीमित रहेगी और अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक ही असर दिखाई देगा. ऐसे में आम घरेलू उपभोक्ताओं को यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा है.

कचे तेल की कीमतों में तेजी आने के बाद कोयले की लागत भी बढ़ गई. इससे बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का खर्च बढ़ा और वितरण कंपनियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ी. बिजली वितरण कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का हवाला देते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग से पीपीएसी में 31 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की अनुमति मांगी थी. लेकिन आयोग ने कंपनियों की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और केवल 2.4 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी. इससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 32.34 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है. वहीं अधिक खपत की स्थिति में भी उन्हें 50 प्रतिशत तक की राहत दी जाती है. ऐसे उपभोक्ताओं पर पीपीएसी बढ़ोतरी का प्रभाव लगभग नहीं के बराबर रहेगा. दिल्ली के लगभग 41.66 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर PPAC का असर पड़ सकता है. इनमें बड़ी संख्या कमर्शियल और इंडस्ट्रियल श्रेणी के उपभोक्ताओं की है. माना जा रहा है कि बढ़ी हुई लागत का प्रभाव मुख्य रूप से इसी वर्ग पर देखने को मिलेगा.

जन-भागीदारी से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर! दिल्ली के 28 घाटों पर मेगा सफाई अभियान

नई दिल्ली । दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी के 28 घाटों पर यमुना की सफाई का एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया।

इस अभियान का मकसद नदी और उसके आस-पास के इलाकों की सफ़ाई करना था। गुप्ता ने इस अभियान में लोगों की अलग-अलग तरह की भागीदारी पर ज़ोर देते हुए कहा कि रविवार को दिल्ली के 28 घाटों पर यमुना की सफ़ाई का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया, जिसमें हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। मैंने देखा कि बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, सभी ने इस सफ़ाई अभियान में भाग लिया। सफ़ाई अभियान के दौरान मिले कचरे के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि वहाँ हमें प्लास्टिक की थैलियाँ, पूजा-पाठ का सामान और टूटी हुई मूर्तियाँ मिलीं। इसका क्या समाधान है? मुझे लगता है कि इस तरह के सफ़ाई अभियान नियमित रूप से चलाने की ज़रूरत है। उन्होंने आगे कहा कि रिवरफ़्रंट इलाकों में मिलने वाले कचरे के प्रकार के हिसाब से ही कचरा प्रबंधन की रणनीतियां बनाई जाएंगी। गुप्ता ने समझाया कि वहां मिलने वाली हर तरह की चीज़ के लिए हमें अलग-अलग तरह से कचरा प्रबंधन करना होगा। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से यमुना को साफ़ रखने में सक्रिय रूप से शामिल होने और पर्यावरण से जुड़ी मौजूदा पहलों का समर्थन करने की अपील की। दिल्ली सरकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करके यमुना को साफ़ करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली को साफ़-सुथरा और हरा-भरा बनाने के मकसद से पेड़-पौधे लगाकर नदी के किनारे को फिर से बेहतर बनाने की योजना बना रही है। गुप्ता ने पूजा-पाठ की चीज़ों के निपटारे के बारे में भी सीधे तौर पर अपील की। उन्होंने इन चीज़ों की पवित्रता और इस्तेमाल के बाद इनके ज़िम्मेदार तरीके से निपटारे की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। रविवार को मुख्यमंत्री ने खुद इस अभियान में हिस्सा लिया और वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दिल्ली के 28 यमुना घाटों की सफाई के लिए आगे आने वाले सभी युवाओं, सफाई कर्मचारियों, वॉलंटियर्स, सामाजिक संगठनों और इस अभियान से जुड़े 500 से ज़्यादा संस्थानों और एनजीओ पार्टनर्स का दिल से धन्यवाद।

तुगलकाबाद आगजनी के तीनों आरोपितों पर लगेगा मकोका! एविल इंजेक्शन की तस्करी बनी तीन मौतों की वजह

दक्षिणी दिल्ली। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून को आग लगाने की घटना में गिरफ्तार तीनों बालिग आरोपितों निरंजन, राजकुमार व सरिता को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस आरोपितों पर मकोका लगाने का तैयारी भी कर रही है। आरोपित संगठित गिरोह के तौर पर नशे के कारोबार के साथ ही अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे। आरोपितों से अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। एविल वायल के साथ नींद की गोलियां चिपकाकर ई-रिक्शा चालकों, नाबालिगों को गली-गली बिकवाते थे। एविल इंजेक्शन की 400 वायल की एक पेटी आरोपितों ने तुगलकाबाद गली नंबर एक में उक्त इमारत में रहने वाले दीपक को दी थी। वह बार-बार इसे पुलिस को देने की बात कर रहा था, जिसको लेकर सरिता व दीपक से कई बार बहस भी हो चुकी थी। इसी अदावत में दीपक की स्कूटी जलवाई गई, लेकिन आग पार्किंग में खड़ी अन्य बाइकों तक फैल गई। घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी।

पीएम मोदी बोले- टेक्नोलॉजी हमारे संबंधों का आधार, भारत-स्लोवाकिया के बीच कई अहम समझौते

नई दिल्ली । भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्लोवाकियाई समकक्ष रॉबर्ट फिचो के बीच ब्रातिस्लावा कैसल में अहम मुलाकात हुई। दोनों के अहम बैठक हुई, जिसके बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया की मदद का आभार भी जताया। साझा वक्तव्य के दौरान पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई गति देने के बारे में विस्तार से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी में हुई प्रगति हमारे लिए संतोष की बात है। हालाँकि, हमारी क्षमताएं बहुत अधिक हैं और हमारी आकांक्षाएं उससे भी कहीं अधिक हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको अनुभवी नेता होने के साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया के संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है कि आज उनसे मिलकर हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का शुभ अवसर मिला।

मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा कि, इंडिया-ईयू, एफटीए को अंतिम रूप देने में स्लोवाकिया से मिले सहयोग के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हम इसके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करेंगे ताकि दोनों देशों के उद्योग, स्टार्टअप्स और ट्रेडर्स इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए समझौते इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनाएंगे। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है। हमारा मानना है कि एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी भी दोनों देशों के लिए मुख्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। हमने इस क्षेत्र में दोनों देशों की इंडस्ट्रीज और एक्सपर्ट्स के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे साझा विकास, साझा उत्पादन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। वैश्विक मंच पर भी भारत और स्लोवाकिया करीबी सामंजस्य से आगे बढ़ रहे हैं। हम सहमत हैं कि सभी विवादों और तनावों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए।

सम्पादकीय...

वैश्विक समाधान

फ्रांस के नीस शहर में आयोजित "भारत इनोवेट्स 2026" केवल एक निवेश सम्मेलन नहीं था, बल्कि यह उस बदलते भारत की झलक थी जो अब वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल बाजार के रूप में नहीं, बल्कि नवाचार और समाधान के केंद्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा इस कार्यक्रम का संयुक्त उद्घाटन भारत और फ्रांस के रणनीतिक संबंधों के साथ-साथ भारत की बढ़ती आर्थिक महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक था। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मंच पर आने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के प्रमुख वेंचर कैपिटल निवेशकों और भारतीय उद्यमियों के साथ विस्तृत बातचीत की। ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल, उद्यमी रॉनी स्क्रूवाला तथा कई अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की उपस्थिति ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि भारत अब केवल विदेशी पूंजी की तलाश में नहीं है, बल्कि वह वैश्विक निवेशकों को एक ऐसी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहा है जो भविष्य की तकनीकों और नवाचारों को आकार देने की क्षमता रखती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आज दुनिया से समाधान खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को समाधान देने वाला राष्ट्र बन रहा है। यह कथन केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक यात्रा का सार भी था। डिजिटल भुगतान, आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है।एक समय था जब भारत को मुख्य रूप से सस्ते श्रम और बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देखा जाता था। विदेशी कंपनियां भारत में अपने उत्पाद बेचने आती थीं और भारत की भूमिका मुख्यतः उपभोक्ता अर्थव्यवस्था की होती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भारतीय स्टार्टअप स्वास्थ्य, शिक्षा, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में ऐसे समाधान विकसित कर रहे हैं जिन्हें दुनिया के अन्य देश भी अपनाने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत इनोवेट्स 2026 के दौरान लगभग 1.5 अरब डॉलर के निवेश प्रस्तावों और साझेदारियों की चर्चा ने यह साबित किया कि वैश्विक निवेशक भारत की संभावनाओं को लेकर आश्वस्त हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। दूसरा, यहां युवा आबादी का बड़ा हिस्सा तकनीक और उद्यमिता के क्षेत्र में सक्रिय है। तीसरा, सरकार लगातार स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने वाली नीतियां लागू कर रही है। हालांकि इस सफलता के पीछे केवल आर्थिक कारक ही नहीं हैं। यह निवेश कूटनीति का भी परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के विभिन्न देशों के साथ आर्थिक साझेदारी को नई दिशा दी है। फ्रांस के साथ संबंध इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान, हरित ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। भारत इनोवेट्स 2026 इसी सहयोग का नया अध्याय माना जा सकता है। फ्रांस और भारत दोनों ऐसे समय में एक-दूसरे के करीब आए हैं जब वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है। अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बदलाव और नई तकनीकों की दौड़ ने देशों को नए साझेदार खोजने के लिए प्रेरित किया है। फ्रांस भारत को एक विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझेदार के रूप में देखता है, जबकि भारत यूरोप में फ्रांस को अपने सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगियों में गिनता है। इस सम्मेलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि यहां केवल पूंजी निवेश की बात नहीं हुई, बल्कि नवाचार आधारित साझेदारी पर जोर दिया गया। आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में केवल धन पर्याप्त नहीं है। ज्ञान, अनुसंधान, तकनीक और प्रतिभा भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भारत इस वास्तविकता को समझते हुए अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।हालांकि भी चुनौतियां कम नहीं हैं। भारत के स्टार्टअप क्षेत्र को अभी भी पूंजी तक समान पहुंच, अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश, नियामकीय सरलता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई स्टार्टअप शुरुआती सफलता के बाद टिकाऊ व्यवसाय मॉडल विकसित करने में संघर्ष करते हैं। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में भारत को अभी काफी निवेश और कौशल विकास की आवश्यकता है। यही कारण है कि भारत इनोवेट्स 2026 जैसे कार्यक्रम केवल निवेश आकर्षित करने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करने का मंच भी हैं। इन आयोजनों के माध्यम से भारत यह संदेश दे रहा है कि वह केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि उसके भविष्य को आकार देने में भी भूमिका निभाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों की संयुक्त उपस्थिति ने यह भी संकेत दिया कि आर्थिक सहयोग अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। यह नवाचार, प्रौद्योगिकी, हरित विकास और रणनीतिक साझेदारी का व्यापक ढांचा बन चुका है। आने वाले वर्षों में यदि भारत अपने नवाचार इकोसिस्टम को और मजबूत करता है, तो वह दुनिया की अग्रणी तकनीकों और आर्थिक शक्तियों में शामिल हो सकता है। अंततः, भारत इनोवेट्स 2026 एक सम्मेलन से कहीं अधिक था। यह उस परिवर्तन की कहानी है जिसमें भारत एक विशाल बाजार से आगे बढ़कर एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यदि यह गति बनी रहती है, तो आने वाले दशक में भारत न केवल निवेश का प्रमुख गंतव्य होगा, बल्कि उन समाधानों का स्रोत भी बनेगा जो दुनिया की कई जटिल समस्याओं का उत्तर प्रदान कर सकते हैं।

फ्रांस के साथ ही स्लोवाकिया में बजा मोदी का डंका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खासतौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मोदी का स्वागत जिस भूतपूर्व अंदाज में किया, उसने दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि मोदी वैश्विक राजनीति के सबसे बड़े धुरंधरों में गिने जाते हैं। इस यात्रा के दौरान यूरोप की धरती पर भारत की बढ़ती ताकत और मोदी की वैश्विक लोकप्रियता हर तरफ दिखाई दी। फ्रांस से लेकर स्लोवाकिया तक भारतीय समुदाय ने अपने प्रधानमंत्री का जिस उत्साह, जोश और भारतीय अंदाज में स्वागत किया, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। हाथों में तिरंगा, भारत माता के जयकारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने यह दिखा दिया कि दुनिया भर में बसे भारतीय आज अपने देश की बढ़ती प्रतिष्ठा पर गर्व महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि मोदी की यह यात्रा केवल एक विदेशी दौरा नहीं रही, बल्कि दुनिया के सामने नए और शक्तिशाली भारत का दमदार प्रदर्शन बन गई। देखा जाये तो यूरोप की धरती पर मोदी का स्वागत जिस गर्मजोशी, रणनीतिक सम्मान और राजनीतिक विश्वास के साथ हुआ, उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। विशेष रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को जिस तरह भारतीय रंग दिया, वह भारत की बढ़ती सांस्कृतिक और रणनीतिक ताकत की स्वीकारोक्ति थी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो, मोदी और मैक्रों की आत्मीयता और नाइस में आयोजित भारत इनोवेट्स सम्मेलन ने यह साबित किया कि भारत और फ्रांस का रिश्ता अब केवल हथियार खरीद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह तकनीक, नवाचार, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैश्विक नेतृत्व की साझेदारी में बदल चुका है। मोदी और मैक्रों की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण संदेश उभरा, वह था रक्षा सहयोग का नया प्रारूप। भारत ने साफ कर दिया कि अब वह केवल विदेशी हथियारों का खरीदार नहीं रहेगा। राफेल कार्यक्रम को लेकर भारत ने सह विकास, सह डिजाइन, सह उत्पादन और सह निर्माण की नीति अपनाकर अपनी रणनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान इस बात का संकेत है कि मोदी सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को निर्णायक रूप से आगे बढ़ा रही है। देखा जाये तो राफेल केवल एक युद्धक विमान नहीं है बल्कि यह भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से मौजूद 36 राफेल विमानों ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को बदल दिया है। अब भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों का समझौता और भविष्य में बड़े राफेल कार्यक्रम की तैयारी यह दिखाती है कि भारत हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक अपनी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। इन विमानों को लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता, अत्याधुनिक सेंसर प्रणाली और बहु भूमिका युद्ध कौशल भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ निर्णायक बढ़त देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राफेल का निर्माण और उसके पुर्जों का उत्पादन भारत में करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ रही है। इसके जरिये भारत विश्व का प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र बन सकता है। इससे न केवल लाखों कुशल रोजगार पैदा होंगे बल्कि भारत का रक्षा औद्योगिक ढांचा भी मजबूत होगा। यह बदलाव दक्षिण एशिया की सामरिक राजनीति पर गहरा प्रभाव डालेगा। अब तक हथियार आयात पर निर्भर भारत धीरे धीरे रक्षा निर्यातक राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में और अधिक झुकता दिखाई देगा। साथ ही फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी केवल रक्षा तक सीमित नहीं है। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप 2030, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्य समूह, आर्थिक सुरक्षा संवाद और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग जैसे फैसले इस बात का संकेत हैं कि दोनों देश आने वाले दशकों की वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिस्पर्धा को साथ मिलकर आकार देना चाहते हैं।

नाइस में आयोजित भारत इनोवेट्स सम्मेलन इस यात्रा का सबसे प्रतीकात्मक क्षण साबित हुआ। एक सौ बीस से अधिक भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भागीदारी और वैश्विक निवेशकों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल बाजार नहीं, बल्कि नवाचार का वैश्विक केंद्र बन चुका है। मोदी ने सही कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता केवल हितों का नहीं, बल्कि साझा दृष्टि का रिश्ता है। मैक्रों द्वारा भारत की चंद्रयान उपलब्धि और नवाचार क्षमता की खुली प्रशंसा इस बात का प्रमाण है कि विश्व अब भारत को तकनीकी महाशक्ति के रूप में देखने लगा है। फ्रांस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू था अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहयोग। छोटे और उन्नत परमाणु रिएक्टरों पर सहयोग तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में साझेदारी भारत को भविष्य की रणनीतिक तकनीकों में अग्रणी स्थान दिला सकती है। यही कारण है कि भारत फ्रांस संबंध अब पारंपरिक कूटनीति से निकलकर भविष्य की वैश्विक व्यवस्था की धुरी बनते दिख रहे हैं। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा ने भारत की यूरोपीय रणनीति को और गहराई दी। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्लोवाकिया यात्रा थी और इसी तथ्य ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के साथ हुई बैठकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब यूरोप के छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देशों के साथ भी मजबूत संबंध बना रहा है। भारत और स्लोवाकिया के बीच संबंधों को व्यापक साझेदारी का दर्जा दिया जाना एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम है। यह मध्य यूरोप में भारत की बढ़ती उपस्थिति का संकेत है। वाहन निर्माण, रेलवे उपकरण, निवेश, उभरती तकनीक और व्यापार के क्षेत्रों में सहयोग भारत को यूरोपीय संघ के भीतर नई आर्थिक और रणनीतिक पहुंच देगा। विशेष रूप से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्र लागू करने की दिशा में सक्रिय दिख रहा है, जिसका लाभ भारतीय उद्योग और निर्यात को मिलेगा।

देखा जाये तो मोदी की यह पूरी यूरोपीय यात्रा दरअसल भारत की बहुस्तरीय कूटनीति का उदाहरण है। एक ओर फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के साथ रक्षा और तकनीकी गठजोड़ को नई ऊंचाई दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्लोवाकिया जैसे देशों के माध्यम से यूरोप में भारत का प्रभाव क्षेत्र विस्तारित किया जा रहा है। यह नीति भारत को ग्लोबल साउथ और पश्चिमी शक्तियों के बीच एक संतुलित, विश्वसनीय और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज दुनिया के बदलते भू राजनीतिक माहौल में भारत जिस आत्मविश्वास के साथ अपनी रणनीतिक दिशा तय कर रहा है, उसके केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सक्रिय और दूरदर्शी कूटनीति है। चाहे रक्षा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हो, वैश्विक नवाचार में नेतृत्व की महत्वाकांक्षा हो या यूरोप के साथ बहुआयामी साझेदारी का विस्तार, मोदी सरकार ने हर मोर्चे पर भारत की स्थिति को मजबूत किया है।

सफलता की कहानी

उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना आधी आबादी के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन का एक बेहद मजबूत और जीवंत माध्यम बनकर उभरी है। इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत अकेले बरेली जनपद में अब तक कुल 74,153 ऋण वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से 22,054 ऋण विशेष रूप से महिलाओं को उनके स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा महिलाओं के आवेदनों को सर्वाधिक प्राथमिकता के आधार पर बैंकों को भेजकर त्वरित ऋण स्वीकृति सुनिश्चित कराई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। बरेली की ये 22 हजार से अधिक आत्मनिर्भर महिलाएं सिलाई-कढ़ाई, टिफिन सेवा, अचार-मुरब्बा निर्माण और पापड़-बड़ी निर्माण जैसे विभिन्न लघु व्यवसायों को अपनाकर न केवल अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं, बल्कि अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी एक युगांतरकारी बदलाव ला रही हैं। इस सफलता की कई अनूठी मिसालें बरेली के कोने-कोने में बिखरी हैं, जहाँ सीबीगंज की पिंकी जायसवाल ने पहले चरण में मिले 10 हजार रुपये के ऋण से सिलाई मशीन की मरम्मत कराकर अपना सिलाई का व्यवसाय शुरू किया और फिर समय पर भुगतान कर 20 हजार रुपये का दूसरा ऋण प्राप्त किया, जिससे वे आज एक अन्य महिला सहायक को रोजगार देने में सक्षम हुई हैं। इसी तरह प्रेमनगर की गुड़िया यादव ने इस वित्तीय सहायता से अपनी टिफिन सेवा की शुरुआत की, जो आज प्रतिदिन लगभग 100 ग्राहकों तक पहुंच रही है, जबकि कालीबाड़ी की रचना गुप्ता ने अचार-मुरब्बे के कारोबार से प्रतिमाह लगभग 15 हजार रुपये की बचत सुनिश्चित की है और हरूनगला की पुष्पा ने पारंपरिक पापड़-बड़ी उद्योग को विस्तार देकर अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। बरेली जनपद का यह अनुकरणीय और प्रेरक मॉडल वास्तव में उस व्यापक बदलाव की एक छोटी सी बानगी है, जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर पर देखने को मिल रहा है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के वैश्विक संकट के बाद शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना पूरे प्रदेश के रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों और छोटे दुकानदारों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुई है, जिसने उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराकर बिना किसी गारंटी के आसान कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराया। उत्तर प्रदेश शासन ने इस योजना को एक बड़े मिशन के रूप में अंगीकार किया और नगर निकायों से लेकर बैंकिंग प्रणाली तक एक बेहद सुदृढ़, पारदर्शी और संवेदनशील व्यवस्था तैयार की, जिससे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक इसका लाभ बिना किसी बाधा के पहुँच सका। योजना की प्रगतिशील रूपरेखा के तहत पहले चरण में 10 हजार रुपये, दूसरे चरण में 20 हजार रुपये तथा तीसरे चरण में 50 हजार रुपये तक का ऋण क्रमिक रूप से दिया जाता है, जिससे लाभार्थियों ने वित्तीय अनुशासन के साथ न केवल अपना व्यवसाय स्थापित किया अपितु उसे आगे बढ़ाने में भी सक्षम हो सके हैं। उत्तर प्रदेश आज इस योजना के प्रभावी और जमीनी क्रियान्वयन के कारण पूरे देश में अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है, जहाँ छोटे कस्बों से लेकर बड़े महानगरों तक के फेरीवाले, सब्जी विक्रेता और खोमचे वाले मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।

ट्रंप-नेतन्याहू तनाव और ईरान समझौता: पश्चिम एशिया की बदलती राजनीति का संकेत

भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष चिंता का विषय रही क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता सफल होता है, तो इससे वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। तेल की कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बढ़ेगी और व्यापारिक अनिश्चितता कम हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रमुख पक्ष इस समझौते को स्वीकार करें और उसे लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएं। इतिहास यह बताता है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करना आसान नहीं है। यहां कई ऐसे मुद्दे हैं जो दशकों से अनसुलझे हैं। इसलिए किसी भी समझौते को अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। फिर भी संवाद और कूटनीति की दिशा में उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण होता है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के प्रति नाराजगी और अमेरिका-ईरान समझौते की दिशा में बढ़ती पहल यह दर्शाती है कि पश्चिम एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है।

पश्चिम एशिया लंबे समय से वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है। यहां होने वाली हर घटना का असर केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करता है। हाल के दिनों में अमेरिका, ईरान और इज़राइल से जुड़ा एक नया घटनाक्रम सामने आया है, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार कर लिया गया है। लेकिन इस घोषणा से अधिक चर्चा उस नाराजगी की हो रही है, जो ट्रंप ने इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के प्रति जाहिर की। रिपोर्टों के अनुसार, ट्रंप उस समय बेहद नाराज हो गए जब इज़राइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में सैन्य कार्रवाई की, जबकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने की दिशा में बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। माना जा रहा है कि यह हमला समझौते की घोषणा से ठीक पहले हुआ, जिससे पूरे कूटनीतिक प्रयास पर संकट पैदा होने की आशंका बढ़ गई। ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे समय में हमला करना समझदारी भरा कदम नहीं था। यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को लंबे समय से घनिष्ठ राजनीतिक सहयोगी माना जाता रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका ने कई ऐसे फैसले लिए थे, जिन्हें इज़राइल के हितों के अनुकूल माना गया था। यरूशलम को इज़राइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना और मध्य पूर्व नीति में इज़राइल के पक्ष में स्पष्ट झुकाव दिखाना इसके प्रमुख उदाहरण रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति ने यह संकेत दिया है कि दोनों नेताओं की रणनीतिक प्राथमिकताओं में अंतर मौजूद है। फरवरी 2026 में शुरू हुआ अमेरिका-ईरान संघर्ष धीरे-धीरे पूरे क्षेत्र में फैल गया। अमेरिकी और इज़राइली हमलों के जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य सक्रियता बढ़ाई। खाड़ी देशों में तनाव बढ़ा, समुद्री व्यापार प्रभावित हुआ और तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। विश्व अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही थी और इस युद्ध ने ऊर्जा बाजार को और अस्थिर बना दिया। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दुनिया की चिंता बढ़ गई थी। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान बार-बार संकेत देता रहा कि यदि उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वह इस मार्ग पर प्रभाव डाल सकता है। यही कारण था कि अमेरिका समेत कई देशों के लिए युद्ध को जल्द समाप्त करना आवश्यक हो गया। युद्ध के शुरुआती चरण में ट्रंप प्रशासन ने कठोर रुख अपनाया था। लेकिन समय बीतने के साथ यह स्पष्ट होने लगा कि लंबा संघर्ष अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए भी चुनौती बन सकता है। अमेरिका में बढ़ती ईंधन कीमतें, वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और आगामी राजनीतिक चुनौतियों ने ट्रंप प्रशासन को कूटनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान कतर, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देशों ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई और अमेरिका तथा ईरान के बीच संवाद का रास्ता खुला। दूसरी ओर, इज़राइल की चिंताएं अलग हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू लंबे समय से यह कहते रहे हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके क्षेत्रीय सहयोगी संगठन इज़राइल की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। उनके अनुसार केवल अस्थायी समझौते से समस्या का समाधान नहीं होगा। यही कारण है कि इज़राइल सैन्य दबाव बनाए रखने के पक्ष में दिखाई देता है। लेबनान में हुई कार्रवाई को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इज़राइल का मानना है कि हिज्बुल्लाह जैसे संगठनों को कमजोर किए बिना क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिए उस समय यह हमला बेहद संवेदनशील था क्योंकि वह ईरान के साथ एक समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में इज़राइल की कार्रवाई ने दोनों देशों की रणनीतिक सोच में मौजूद अंतर को उजागर कर दिया। ईरान की स्थिति भी कम जटिल नहीं है। कई महीनों तक चले सैन्य हमलों और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद उसने पूरी तरह झुकने से इनकार किया। हालांकि युद्ध ने उसकी अर्थव्यवस्था और आंतरिक व्यवस्था पर दबाव अवश्य बढ़ाया है। इसलिए तेहरान बातचीत के लिए तैयार दिखाई देता है, लेकिन वह अपने परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय हितों को लेकर कोई बड़ा समझौता करने के लिए भी आसानी से तैयार नहीं होगा। इस पूरे संकट का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। तेल की कीमतों में वृद्धि ने दुनिया भर में महंगाई बढ़ाने का काम किया। कई देशों में ऊर्जा और परिवहन लागत बढ़ गई। समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरे के कारण आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुईं। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति विशेष चिंता का विषय रही क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी क्षेत्र से पूरा होता है। यदि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित समझौता सफल होता है, तो इससे वैश्विक बाजारों को राहत मिल सकती है। तेल की कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बढ़ेगी और व्यापारिक अनिश्चितता कम हो सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रमुख पक्ष इस समझौते को स्वीकार करें और उसे लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाएं। इतिहास यह बताता है कि पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करना आसान नहीं है। यहां कई ऐसे मुद्दे हैं जो दशकों से अनसुलझे हैं। इसलिए किसी भी समझौते को अंतिम समाधान नहीं माना जा सकता। फिर भी संवाद और कूटनीति की दिशा में उठाया गया हर कदम महत्वपूर्ण होता है। डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू के प्रति नाराजगी और अमेरिका-ईरान समझौते की दिशा में बढ़ती पहल यह दर्शाती है कि पश्चिम एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। यह केवल युद्ध और शांति की कहानी नहीं, बल्कि उन जटिल हितों की भी कहानी है जो इस क्षेत्र की राजनीति को आकार देते हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह समझौता वास्तव में स्थायी शांति की शुरुआत बनता है या फिर पश्चिम एशिया एक बार फिर नए तनावों की ओर बढ़ता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इसी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां होने वाले निर्णयों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है।

संभावित समझौते को लेकर परस्पर विरोधी दावों ने विश्व निवेशकों को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया

वैश्विक स्तरपर वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में वित्तीय बाजार केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक घटनाओं से भी संचालित हो रहे हैं।अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव तथा युद्धविराम एवं संभावित समझौते को लेकर परस्पर विरोधी दावों ने विश्व निवेशकों को असमंजस की स्थिति में ला खड़ा किया है। एक ओर अमेरिका बार-बार यह संकेत दे रहा है कि 14 जून 2026 को शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है,वहीं दूसरी ओर ईरान इसे केवलप्रारंभिक वार्ता बताते हुए अपनी शर्तें पूरी न होने की बात कह रहा है। ईरान के भीतर भी संभावित समझौते के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस अनिश्चित वातावरण का सीधा प्रभाव वैश्विक पूंजी प्रवाह,निवेशक विश्वास और शेयर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के 14 जून 2026 को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून 2026 के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों से 62,853 करोड़ रुपए की भारी निकासी की है। यह केवल भारतीय बाजार की कहानी नहीं बल्कि वैश्विक पूंजी के बदलते रुझानों, जोखिम की बढ़ती धारणा और निवेशकों की सुरक्षित परिसंपत्तियों की ओर वापसी का संकेत है। मैं एडवोकेशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि, विदेशी निवेशकों की यह बिकवाली किसी एक कारण का परिणाम नहीं है,बल्कि अनेक वैश्विक और घरेलू कारकों का संयुक्त प्रभाव हैसबसे प्रमुख कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति मानी जा रही है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और वहां ब्याज दरों के उच्च स्तरपर बने रहने से वैश्विक निवेशकों को सुरक्षित और निश्चित प्रतिफल के अवसर उपलब्ध हो रहेहैं।सामान्यतःजब अमेरिका में जोखिम- रहित प्रतिफल बढ़ता है तो उभरते बाजारों, विशेषकर भारत जैसे देशों में निवेश का आकर्षण कुछ कम हो जाता है। साथियों, विदेशी फंड प्रबंधक जोखिम लेकर उभरते बाजारों में निवेश करने के बजाय अमेरिकी सरकारी बॉन्ड तथा डॉलर आधारित परिसंपत्तियों में धन लगाना अधिक सुरक्षित समझते हैं। परिणामस्वरूप भारत सहित कई उभरते बाजारों से पूंजी निकासी तेज हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता है। अमेरिका-ईरान तनाव, तेल आपूर्ति मार्गों को लेकर चिंताएं, ऊर्जा कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव और वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों ने निवेशकों की जोखिम लेने की क्षमता को कम किया है। जब भी वैश्विक स्तर पर युद्ध या संघर्ष की आशंका बढ़ती है, निवेशक तथाकथित "सेफ हेवन" परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं। अमेरिकी डॉलर, सोना और विकसित देशों के सरकारी बॉन्ड ऐसे समय में अधिक आकर्षक बन जाते हैंइसके विपरीत उभरते बाजारों में निवेश अपेक्षाकृतजोखिमपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि जून के पहले पखवाड़े में भारतीय शेयर बाजारों से भारी विदेशी पूंजी निकासी देखने को मिली साथियों एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि भारतीय शेयर बाजार का ऊंचा मूल्यांकन और मुनाफावसूली है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, कॉर्पोरेट आय में वृद्धि, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार और घरेलू निवेशकों की सक्रिय भागीदारी के कारण भारतीय बाजारों में उल्लेखनीय तेजी देखी गई। अनेक प्रमुख सूचकांक ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर पहुंचे। ऐसी स्थिति में विदेशी निवेशकों ने अपने निवेश पर लाभ सुरक्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली की। वैश्विक फंड प्रबंधक अक्सर उन बाजारों में लाभ बुक करते हैं जहां उन्हें लगता है कि मूल्यांकन काफी ऊंचा हो चुका है और आगे की वृद्धि सीमित हो सकती है। भारतीय बाजार में हालिया बिकवाली को इसी दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा हैइसके अतिरिक्त भारतीय रुपये की कमजोरी भी विदेशी निवेशकों के लिए चिंता का विषय रही है। यदि कोई विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों में लाभ कमाता है लेकिन उसी अवधि में रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले घट जाता है, तो वास्तविक डॉलर आधारित रिटर्न कम हो जाता है। यही कारण है कि मुद्रा जोखिम भी विदेशी निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करता है। 2026 में रुपये की कमजोरी ने विदेशी निवेशकों की चिंता को और बढ़ाया है। साथियों एनएसडीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। जहां 2026 में फरवरी को छोड़कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हर महीने भारतीय शेयरों के शुद्ध विक्रेता रहे हैं। जनवरी में उन्होंने लगभग 35,962 करोड़ रुपए की निकासी कीफरवरी में स्थिति थोड़ी सुधरी और लगभग 22,615 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो 17 महीनों में सबसे बड़ा मासिक प्रवाह था। लेकिन मार्च में रिकॉर्ड 1.17 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली हुई। अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए और मई में 32,963 करोड़ रुपए की निकासी दर्ज की गई। जून के पहले पंद्रह दिनों में ही 62,853 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। इसके साथ ही वर्ष 2026 में कुल विदेशी निकासी लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पूरे वर्ष 2025 की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ से भी कहीं अधिक है। यह आंकड़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उठाए गए हैं।

साथियों यह आंकड़े दर्शाते हैं कि विदेशी निवेशकों का रुख केवल अल्पकालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक रणनीतिक पुनर्संतुलन का हिस्सा है। हाल के महीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कंपनियों और अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारी निवेश आकर्षित हुआ है। अनेक वैश्विक फंड उभरते बाजारों से धन निकालकर अमेरिकी तकनीकी कंपनियों और एआई से संबंधित अवसरों में निवेश कर रहे हैं। इससे भारत सहित कई देशों के शेयर बाजारों पर दबाव बना हैहालांकि विदेशी निवेशकों की इस लगातार बिकवाली के बावजूद भारतीय शेयर बाजार पूरी तरह से धराशायी नहीं हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों की मजबूत भागीदारी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में म्यूचुअल फंड निवेश, व्यवस्थित निवेश योजना, पेंशन फंड और बीमा कंपनियों के निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। घरेलू निवेशकों ने विदेशी निवेशकों द्वारा बेचे जा रहे शेयरों को बड़े पैमाने पर खरीदा है। यही कारण है कि बाजार में अस्थिरता तो बढ़ी है, लेकिन व्यापक गिरावट नहीं आई। भारतीय पूंजी बाजार को यह संरचनात्मक मजबूती पिछले दशक की तुलना में कहीं अधिक सशक्त दिखाई देती है। साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से यह स्थिति एक महत्वपूर्ण संकेत भी देती है। पहले विदेशी निवेशकों की बिकवाली का सीधा प्रभाव बाजार पर गंभीर रूप से पड़ता था, लेकिन अब घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा वित्तीय परिसंपत्तियों की ओर आ रहा है। इससे भारतीय बाजारों की विदेशी पूंजी पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है।

हालांकि विदेशी निवेश अभी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन घरेलू निवेशकों की बढ़ती भूमिका बाजार को स्थिरता प्रदान कर रही है।आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो विदेशी पूंजी का निरंतर बहिर्वाह चालू खाते के घाटे, रुपये की विनिमय दर और पूंजी बाजार की तरलता पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक और नीति निर्माता विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपायों पर काम कर रहे हैं। हाल के महीनों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बॉन्ड बाजार में पहुंच बढ़ाने और विदेशी निवेश नियमों को सरल बनाने जैसे कदम उठाए गए हैं ताकि वैश्विक निवेशकों का विश्वास बना रहे। साथियों, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की दृष्टि से आने वाले सप्ताह अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अमेरिका-ईरान वार्ता का परिणाम, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति, जापान के केंद्रीय बैंक के निर्णय और वैश्विक आर्थिक वृद्धि के संकेतक पूंजी प्रवाह की दिशा तय करेंगे। यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम होता है और तेल कीमतों में स्थिरता आती है तो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह सकारात्मक होगा। वहीं यदि संघर्ष बढ़ता है तो ऊर्जा लागत, मुद्रास्फीति और विदेशी निवेश प्रवाह पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जून 2026 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा की गई 62,853 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली केवल भारतीय शेयर बाजार की घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में चल रहे व्यापक बदलावों का प्रतिबिंब है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती, ऊंची बॉन्ड यील्ड, पश्चिम एशिया का भू-राजनीतिक तनाव, रुपये की कमजोरी, एआई आधारित निवेश अवसरों की ओर वैश्विक पूंजी का झुकाव और भारतीय बाजारों में मुनाफावसूली,इन सभी कारकों ने मिलकर विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार से धन निकालने के लिए प्रेरित किया है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साय पॉकेटस एरा, दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया संपादक : विजय कुमार भाटी, मो : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2011/38862)

सलेमपुर में सरकारी योजनाओं की महाचौपाल- राज्य मंत्री ने बांटे स्वीकृति पत्र और दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल

देवरिया।

केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण अंचलों में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने की मुहिम तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देशन में सोमवार को सलेमपुर तहसील सभागार में सोशल सेक्टर (सामाजिक क्षेत्र) से जुड़े विभिन्न विभागों का एक विशाल जनकल्याणकारी शिविर आयोजित किया गया। ÷सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान÷ की मूल भावना पर आधारित इस विधिक शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश की ग्राम्य विकास राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम उपस्थित रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण-पत्र, पेंशन पत्र और दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल का विधिक वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार समाज के गरीब, पिछड़े, मजलूम और बेसहारा नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए पूरी विधिक प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। अंतिम पायदान पर बैठे पात्र व्यक्ति तक शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना प्रशासनिक मशीनरी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने शिविर में मौजूद समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे फाइलों को दबाने के बजाय सक्रिय होकर प्रत्येक जरूरतमंद को चिन्हित करें, ताकि कोई भी विधिक लाभार्थी लाभ से वंचित न रह सके। प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ आयोजित इस शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से 16 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण-पत्र और 10 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्र सौंपे गए। इसी तरह दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 6 दिव्यांग लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से 7 छात्रों को छात्रवृत्ति पत्र, महिला कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना व निराश्रित महिला पेंशन के 10 लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा 10 छात्र-छात्राओं को वजीफा वितरित किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं शिविर के नोडल सुधीर पाण्डेय के संयोजन में हुए इस सफल आयोजन में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमरेश, पुनीत यादव, अभिषेक जायसवाल सहित बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। प्रशासन के अनुसार, इसी श्रृंखला का अगला शिविर 17 जून को तहसील बरहज में आयोजित होगा।

जनसमस्याओं को लेकर सपा का शक्ति प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर गरजे सपाई

कुशीनगर।

महंगाई, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, खाद-बीज संकट, नीलगायों एवं आवारा पशुओं से किसानों को हो रहे नुकसान, बिजली संकट तथा अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया। पूर्व विधान परिषद सदस्य एवं जिलाध्यक्ष राम अवध यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का भारी जनसमूह उमड़ा। प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारों से जिला मुख्यालय गूंज उठा और बाद में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने कहा कि प्रदेश और देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त है। युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, जबकि किसानों को खाद, बीज और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के हक और सम्मान की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष एवं पडरौना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जबकि शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है और समाजवादी पार्टी उसके संघर्ष की मजबूत आवाज बनेगी। कुशीनगर विधानसभा से सपा नेता राजेश प्रताप राव 'बंटी' ने कहा कि किसानों, नौजवानों और गरीबों की समस्याओं के प्रति सरकार पूरी तरह उदासीन बनी हुई है। आवारा पशुओं से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, बिजली संकट से जनजीवन प्रभावित है और रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करती रहेगी। धरना-प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष एवं फाजिलनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी इलियास अंसारी, पूर्व प्रत्याशी विजेंद्र पाल उर्फ बबलू यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बजरंगी यादव, जिला पदाधिकारी मारकंडेय त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। राजनीतिक जानकारों की मानें तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पूर्व आयोजित यह कार्यक्रम केवल विरोध प्रदर्शन ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक ताकत और चुनावी तैयारी का भी बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है।

कपड़ा डालते समय करंट की चपेट में आए युवक की मौत,बचाने गई पत्नी झुलसी

(मृतक बिन्स राजभर का फाइल फोटो)

भटनी देवरिया।

भटनी क्षेत्र के बभनौली कला गांव में करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसे बचाने गई उसकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार बभनौली कला निवासी बिन्स राजभर घर के छत पर रेंगनी

एक वर्षीय बेटे के सिर से उठा पिता का साया, गांव में शोक

पर कपड़ा डालने गए थे। इसी दौरान वह अचानक विद्युत करंट की चपेट में आ गए। पति को बचाने के प्रयास में उनकी पत्नी प्रतिमा देवी भी करंट की चपेट में आकर झुलस गईं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बिन्स राजभर को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से झुलसी प्रतिमा देवी को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि मृतक का एक वर्ष का बेटा भी है। इस दर्दनाक घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आने से सेवानिवृत्त बैंककर्मी की मौत

तमकुहीराज (कुशीनगर)। राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर सोमवार शाम हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में सेवानिवृत्त बैंककर्मी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार, तमकुहीराज थाना क्षेत्र के माधोपुर बुजुर्ग टोला देवला पोखरा निवासी 65 वर्षीय सत्यनारायण शर्मा पुत्र स्वर्गीय अदालत शर्मा सोमवार शाम अपनी मोटरसाइकिल से तमकुहीराज बाजार जा रहे थे। शाम करीब सवा पांच बजे वह गाजीपुर बैरियर स्थित टाटा मोटर्स के समीप पहुंचे थे। इसी दौरान स्क्रैप लदा एक ट्रक, जो गोवाहाटी से पंजाब की ओर जा रहा था, सड़क किनारे वाहन को पीछे कर रहा था। बताया जाता है कि ट्रक चालक ने पर्याप्त सावधानी नहीं बरती, जिसके चलते बाइक सवार सत्यनारायण शर्मा ट्रक के पिछले पहिए की चपेट में आ गए। हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की जानकारी मिलते ही तमकुहीराज पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी करते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कुशीनगर भेज दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है तथा चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है और तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सत्यनारायण शर्मा के निधन की खबर मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। क्षेत्र के लोगों ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है।

अनियंत्रित होकर गिरी बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल

कुशीनगर। थाना क्षेत्र के तरया बैंकुठ गांव में सोमवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार, तरया बैंकुठ निवासी 36 वर्षीय अवधेश खरवार पुत्र हरिछन खरवार अपनी मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने के लिए घर से गांव के चौराहे की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब तीन बजे रास्ते में उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में अवधेश गंभीर रूप से घायल हो गए और सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्काल उन्हें निजी वाहन से रविंद्र नगर धुस स्थित जिला अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार शुरू किया। डॉक्टरों के अनुसार दुर्घटना में उनके मुंह और पैर में गंभीर चोटें आई हैं तथा उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस भी मामले की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा बाइक का संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। पुलिस दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि दुर्घटना अचानक हुई, जिससे आसपास मौजूद लोग भी कुछ देर के लिए सकते में आ गए। समय रहते उपचार मिलने से घायल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

बाइकों की भिड़ंत में युवक घायल, एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया

भटनी देवरिया। बांस घांटी स्थित केरवनिया पुल के पास दिन सोमवार दोपहर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में एक युवक घायल हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, मोतीपुर टिकैत निवासी बच्चन जायसवाल (45) पुत्र मलई जायसवाल बाइक से किसी कार्य से भटनी बाजार जा रहे थे। इसी दौरान केरवनिया पुल के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा गिरी। हादसे में बच्चन जायसवाल के चेहरे पर गंभीर चोटें आईं।

गड़ौरा बाजार में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई- 70 बकायेदारों के कनेक्शन काटे, 1.10 लाख की वसूली

निचलौल।

क्षेत्र के गड़ौरा बाजार में सोमवार को विद्युत विभाग की ग्रामीण टीम द्वारा चलाए गए विशेष संघन जांच अभियान से बकायेदार उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। ग्रामीण अवर अभियंता मुकेश कुमार के नेतृत्व में विभागीय टीम ने क्षेत्र में व्यापक जांच करते हुए बकाया बिजली बिलों, लोड सत्यापन तथा विद्युत उपयोग की स्थिति का निरीक्षण किया। अवर अभियंता ग्रामीण मुकेश कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान न करने वाले 70 बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य बकायेदारों

में भी खलबली मची रही। जांच के दौरान टीम ने उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए प्रेरित किया गया। जिसके परिणामस्वरूप मौके पर ही कुल 1 लाख 10 हजार रुपये की वसूली भी की गई। इसके अलावा जांच में कई उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक विद्युत भार का उपयोग करने की शिकायतें भी सामने आईं। इस पर कार्रवाई करते हुए पांच उपभोक्ताओं का विद्युत लोड बढ़ाया गया। वहीं, तीन उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते पाए गए। ऐसे मामलों में विभाग ने नियमानुसार उनके कनेक्शन की श्रेणी घरेलू से बदलकर कमर्शियल कर दी गई है। इन्होंने आगे बताया कि राजस्व वसूली बढ़ाने तथा विद्युत व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया है। उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल जमा करने और निर्धारित नियमों के अनुसार ही विद्युत उपयोग करने की अपील की गई है।

दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत तीन युवक घायल

भटनी देवरिया।

भटनी थाना क्षेत्र के जगरनाथ छपरा गांव के पास रविवार देर रात दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में तीन युवक घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार खामपार थाना क्षेत्र के कुकुरघाटी निवासी अनीफ शर्मा (35) व कृष्णा शर्मा (21) एक बाइक से घर लौट रहे थे, जबकि जगरनाथ छपरा निवासी आयुष गुप्ता (20) बाजार से अपने घर जा रहे थे। प्राथमिक विद्यालय के पास दोनों बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस के चालक कामक्ष व ईएमटी चंदन ने घायलों

को प्राथमिक उपचार देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटनी पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

कड़े के लालच में दोस्त बना कातिल- पहले सिर में मारे डंडे, जिंदा न बचे तो बाइक से पेट्रोल डालकर जला डाला

नोएडा । ग्रेटर नोएडा स्थित कासना कोतवाली क्षेत्र में मिले एसी मैकेनिक के जले हुए शव की गुत्थी को पुलिस ने तीन दिन के भीतर सुलझाते हुए उसके ही दोस्त को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान शहजाद उर्फ बिट्टू (19) निवासी गांव दौला राजपुर के रूप में हुई है। आरोपी ने सोने के कड़े हड़पने की नीयत से अपने मित्र की बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में शव को जलाकर उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त खून से सना डंडा, तीन पीली धातु के कड़े और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि 12 जून को गांव चीरसी की नहर के पास एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था। शव आंशिक रूप से जला हुआ था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। बाद में मृतक की पहचान दनकौर थाना क्षेत्र के दौला राजपुर निवासी 23 वर्षीय हुजैफ पुत्र मुजम्मिल के रूप में हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने मामले के खुलासे के लिए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया था। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य जुटाए और मृतक के संपर्कों की पड़ताल की। इसी क्रम में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर सोमवार को शहजाद उर्फ बिट्टू निवासी दौला राजपुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की पूरी वारदात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक हुजैफ और आरोपी शहजाद आपस में घनिष्ठ मित्र थे और दोनों नशा करने के आदी थे।

हुजैफ नया मोबाइल फोन खरीदना चाहता था और एयर कंडीशनर का काम शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी। परिवार वालों द्वारा पैसे नहीं दिए जाने पर उसने कथित तौर पर अपनी मां के चार पीली धातु के कड़े चोरी कर लिए थे। उसने इन कड़ों को बेचने की बात अपने दोस्तों और शहजाद को भी बताई थी। इसी जानकारी के बाद आरोपी की नीयत कड़ों पर खराब हो गई। 12 जून को उसने हुजैफ को कड़े बिकवाने का झांसा दिया और अपनी बाइक पर बैठाकर साथ ले गया। रास्ते में दोनों ने नशा किया। इसके बाद आरोपी उसे सुनसान स्थान की तलाश करते हुए चंद्रावल गांव के पास नहर किनारे ले गया। वहां पहुंचने के बाद शहजाद ने मौका देखकर डंडे से हुजैफ के सिर पर हमला कर दिया। पहले वार से वह जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद आरोपी ने उसके ऊपर कई बार डंडे से प्रहार किए। गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी कड़े लेकर वहां से भाग निकला। हालांकि कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद आरोपी को आशंका हुई कि कहीं हुजैफ जीवित न हो। इस डर से वह दोबारा घटनास्थल पर लौटा। वहां उसने शव की पहचान मिटाने के उद्देश्य से अपनी बाइक से पेट्रोल निकाला और शव पर छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटें तेज होने पर उसे डर लगा कि आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच सकते हैं। इस कारण वह शव को नहर में फेंकने की योजना पूरी किए बिना ही वहां से फरार हो गया।

अयोध्या पहुंची एसआईटी, सात दिन में प्रारंभिक तो 15 दिन में पूरी रिपोर्ट देगी

अयोध्या । श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की दान पेटिका में कथित अनियमितता के मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय एसआईटी सोमवार दोपहर करीब 2 बजकर 53 मिनट पर अयोध्या पहुंच गई। टीम ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया गया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से जांच की मांग किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था। रविवार को अवकाश होने के कारण टीम सोमवार को अयोध्या पहुंची। शासन की ओर से एसआईटी को सात दिनों के भीतर प्रारंभिक आंतरिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जबकि 15 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। टीम मामले से जुड़े सभी तथ्यों, दस्तावेजों और वित्तीय अभिलेखों की बारीकी से जांच करेगी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस प्रकरण को लेकर अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच और उसकी अंतिम रिपोर्ट पर टिकी हैं।

दिल्ली में 15 राउंड फायरिंग - आप कार्यकर्ता की हत्या, सिर-चेहरे-सीने में लगीं 10 गोली

नई दिल्ली । दिल्ली के दयालपुर के नेहरू विहार इलाके में सोमवार की शाम रंगदारी देने से इनकार करने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कारोबारी युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

मृतक की शिनाख्त मोहम्मद राशिद (40) के रूप में हुई है। आरोपियों ने घर के नजदीक आरओ प्लांट के पास राशिद को बेहद नजदीक से कई गोलियां मारीं। बदमाशों ने 12 से 15 राउंड गोलियां चलाईं और वह फरार हो गए।

राशिद के सिर, चेहरे और सीने में करीब 10 गोलियां लगीं। फौरन उनको जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया। राशिद की हत्या की खबर मिलते ही एरिया में सनसनी फैल गई। लोगों की भारी भीड़ उनके घर के पास पहुंच गई।

छह महीने पहले भी मिली थी धमकी

उत्तर-पूर्वी जिला के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। परिवार का आरोप है कि छह माह पहले भी अवैध वसूली देने से इनकार करने पर राशिद पर घर के पास ही आठ से 10 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। उस समय वह बाल-बाल बच गए थे।

जांच के लिए तीन टीम गठित

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। हत्या का मामला दर्ज कर जांच के लिए तीन टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि राजा मेवाती उर्फ अक्को डॉन राशिद से रंगदारी मांग रहा था। इस बीच 26 मई को खुद राजा मेवाती की खजूरी में हत्या हो गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि राशिद की हत्या के पीछे अक्को डॉन गिरोह का हाथ है।

राशिश थे बड़े कारोबारी

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि राशिद अपने परिवार के साथ गली-डी-2, नेहरू विहार में रहते थे। इनके परिवार में पिता हाजी यूनुस, मां, पांच भाई, पत्नी के अलावा पांच बच्चे हैं। राशिद के पिता का प्रॉपर्टी का कारोबार है। वहीं राशिद आरओ प्लांट के अलावा ई-रिक्शा, ऑटो चलवाने का बड़ा काम था।

> **उत्तर-पूर्वी जिला के तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्राइम टीम व एफएसएल को मौके पर बुला लिया गया। परिवार का आरोप है कि छह माह पहले भी अवैध वसूली देने से इनकार करने पर राशिद पर घर के पास ही आठ से 10 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। उस समय वह बाल-बाल बच गए थे।**

नजदीक से मारी गई गोलियां

इनके पास बड़ी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा है। राशिद ने भारत टैक्सी ऑटो की एजेंसी भी ली हुई थी। सोमवार शाम करीब 6.10 बजे वह शेरपुर चौक स्थित अपनी ऑटो की एजेंसी से घर के पास ही मौजूद पानी के प्लांट पर पहुंचा। इस बीच स्कूटी पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने बेहद नजदीक से उस पर कई राउंड गोलियां चला दीं।

इलाके में अफरा तफरी

गोली चलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस बीच बदमाश फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर परिजन बाहर निकले तो खून से लथपथ राशिद को देखा। परिजन फौरन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राशिद की हत्या रंगदारी न देने की वजह से हुई या हत्या किसी और वजह से हुई। इसका खुलासा बाद में हो पाएगा।हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है, जांच के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। -राहुल अलवाल,

सीजेपी के अभिजीत दीपके को युवक ने जड़ा थप्पड़, खींचा गमछा

जयपुर । राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को युवक ने थप्पड़ मारा है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जानकारी के मुताबिक घटना के तत्काल बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया. जयपुर में चल रहे प्रदर्शन के दौरान घटना हुई . बता दें कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी.कार्यक्रम संयोजक दीपक बलियान ने इस संदर्भ में रविवार को बताया था कि यह प्रदर्शन युवाओं, छात्रों, अभिभावकों और आम जनता के मुद्दों पर केंद्रित होगा, जिनमें बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा क्षेत्र में कथित अनियमितताएं, भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक और अन्य जनहित के मुद्दे शामिल हैं. पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके, राष्ट्रीय प्रवक्ता अशुतोष शंका, और कई अन्य नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल थे. पार्टी ने राज्य के निवासियों, छात्रों, युवाओं और अभिभावकों से लोकतांत्रिक अधिकारों और जनहित के मुद्दों का समर्थन करते हुए इस प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी.

ट्रक-कार की टक्कर...उड़े परखचे

एक परिवार के 6 लोगों की गई जान

हरियाणा डेस्क । राजस्थान के बीकानेर जिले में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में हरियाणा के एक ही परिवार के छह लोगों की जान चली गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, हादसा श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में हेमासर फांटे के पास हुआ। कार और ट्रक के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखचे उड़ गए और उसमें सवार सात लोगों में से छह लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची जख्मी हो गई। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

परिवार के सदस्य बीकानेर स्थित मुकाम में बिश्नोई समाज के आराध्य गुरु जम्भेश्वर भगवान के समाधि स्थल के दर्शन कर वापस हरियाणा लौट रहे थे। इसी दौरान हेमासर फांटे के पास उनकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि मृतक फतेहाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जंग खत्म हुई, अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी वापस ले सरकार - कांग्रेस

नई दिल्ली । कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म करने के लिए सहमति बनने के बाद अब सरकार को पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन की कीमतों में की गई बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री इसकी घोषणा फ्रांस से करेंगे या फिर देश लौटकर यह खुशखबरी देंगे? अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन तक जारी रहे युद्ध को समाप्त करने व होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर सहमति बन गई है और दोनों देशों के बीच समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। हमें बताया जा रहा था कि भारत की बेहाल अर्थव्यवस्था की वजह अमेरिका-ईरान की जंग है। हर महंगाई, हर गिरावट और हर परेशानी का दोष सरकार की नीतियों पर नहीं, पश्चिम एशिया के तनाव पर था। अब जब जंग खत्म हो गई है, तो मोदी जी का बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, हमें बताया जा रहा था कि भारत की बेहाल अर्थव्यवस्था की वजह अमेरिका-ईरान की जंग है। हर महंगाई, हर गिरावट और हर परेशानी का दोष सरकार की नीतियों पर नहीं, पश्चिम एशिया के तनाव पर था। अब जब जंग खत्म हो गई है, तो मोदी जी का बहाना भी खत्म हो जाना चाहिए। उनका कहना है, कच्चे तेल के दाम कम होंगे।

आपूर्ति श्रृंखला सामान्य होगी। मांग स्थिर होगी। स्वाभाविक रूप से, इसका फायदा देश के ग्राहकों को भी मिलना चाहिए। मतलब यह कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी और एलएनजी के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, क्या इस खुशखबरी का ऐलान मोदी जी फ्रांस से ही करेंगे? या फिर देश को उनके वापस लौटने का इंतजार करना पड़ेगा?

प्रिंस यादव की मौत पर खान सर ने जताया दुख, कहा- रौशन सर जो कहेंगे वो करने को तैयार

नेशनल डेस्क । ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस की संदिग्ध परिस्थिति में नेपाल में मौत हो गई है। इस घटना पर पटना स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक खान सर की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने अपना वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें वे भावुक नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तीसरे की साजिश हो सकती है। उन्होंने अपील की है पुलिस से त्वरित और पारदर्शी जांच की मांग करें। यह अत्यंत दुखद घटना है। मैं उनके परिवार के दुख को समझ सकता हूं और अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहायता देने को तैयार हूं।

बिना किसी भेदभाव के उचित कार्रवाई की जाएगी

मैं पुलिस से आग्रह करता हूं कि मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच की जाए। इस बीच, बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मामले की जांच वरिष्ठ जिला पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जांच चल रही है। बिना किसी भेदभाव के उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कानून का राज है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।

रौशन आनंद के खिलाफ एफआईआर राजनीति से प्रेरित

रौशन आनंद के वकील निरंजन कुमार सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी गढ़ी हुई, पूर्वनियोजित और राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने दावा किया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) का इस मामले में गलत तरीके से प्रयोग किया गया, क्योंकि आरोपी की मंशा, जानकारी और घटनास्थल पर उपस्थिति जैसे आवश्यक कानूनी तत्व मौजूद नहीं थे।

स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को दिया अपना सर्वोच्च सम्मान, प्रधानमंत्री का ये 33वां ग्लोबल ऑनर

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं. इस दौरान स्लोवाकिया ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास) से सम्मानित किया. अपने सर्वोच्च सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित करने वाला स्लोवाकिया 33वां देश है. स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा. द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (फर्स्ट क्लास) स्लोवाकिया सम्मान है. यह सम्मान स्लोवाकिया के राष्ट्रपति की ओर से विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है. इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने स्लोवाकिया का आभार जताया. पीएम मोदी ने कहा कि इस सम्मान के लिए मैं स्लोवाकिया की जनता और सरकार का आभारी हूं.

यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है. मैं यह पुरस्कार भारत और स्लोवाकिया की अटूट दोस्ती को समर्पित करता हूं. इससे पहले स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए इसे राजनीतिक चमत्कार बताया था. उन्होंने कहा, इतने विविध और जटिल राजनीतिक माहौल में लगातार 12 सालों तक नेतृत्व बनाए रखना असाधारण उपलब्धि है. रॉबर्ट फिको ने आगे कहा कि मैं उस राजनीतिक स्थिरता को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं. मैं आपको बधाई देता हूं कि आप भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री हैं. उन्होंने कहा, यह उपलब्धि एक राजनीतिक चमत्कार के बराबर है, और यह भारत की लोकतांत्रिक ताकत और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है.

भारत-स्लोवाकिया के बीच 11 समझौते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे हैं. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा है. इसके बाद वह फ्रांस में होने वाली जी-7 समिट में शामिल होंगे, जहां उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी. स्लोवाकिया के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच सोमवार को प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए. इन समझौतों से कामगारों के प्रावसन, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और क्वांटम संचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत होगा. पीएम मोदी और पीएम फिको, भारत-यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमत हुए. इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और स्लोवाकिया के बीच रक्षा सहयोग दोनों पक्षों के बीच गहरे आपसी भरोसे और रणनीतिक तालमेल का सबूत है.

सीएम भगवंत मान खालसा पंथ विरोधी करार, श्री अकाल तख्त ने पंजाब विधानसभा के सभी सिख विधायकों को किया तलब

अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को खालसा पंथ विरोधी करार दिया है। श्री अकाल तख्त के जत्थेदार ने पंजाब विधानसभा के सभी सिख विधायकों व कैबिनेट को 29 जून को तलब किया है। नानकशाही संवत 558 के अनुसार 15 जून 2020 को श्री अकाल तख्त साहिब पर पांच सिंह साहिबानों की एक बैठक हुई थी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ शिकायत में मिले आपत्तिजनक वीडियो के मामले पर गंभीरता से चर्चा की गई थी। इस संबंध में जब मुख्यमंत्री भगवंत मान को 15 जनवरी को सचिवालय श्री अकाल तख्त साहिब बुलाया गया था।

ट्रंप-वेंस और गालिबाफ ने शांति समझौते पर किए डिजिटल हस्ताक्षर

वॉशिंगटन । अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते पर दोनों पक्षों ने डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किए जाएंगे, जिसके बाद यह प्रभावी हो जाएगा।

ईरान को कब मिलेगी आर्थिक राहत और प्रतिबंधों में छूट?

उपराष्ट्रपति वेंस ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि समझौते के तहत ईरान को किसी भी प्रकार की आर्थिक राहत या प्रतिबंधों में छूट तभी मिलेगी, जब वह अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक ईरान को कोई धनराशि जारी नहीं की गई है और यह प्रक्रिया पूरी तरह प्रदर्शन आधारित होगी। वेंस के अनुसार, यदि ईरान अपने संवर्धित परमाणु सामग्री के भंडार को कम करने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था को स्वीकार करने जैसे कदम उठाता है, तो अमेरिका प्रतिबंधों में राहत देने पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य ईरान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में दोबारा शामिल होने का अवसर देना है, बशर्ते वह समझौते की शर्तों का पालन करे।

औपचारिक हस्ताक्षर के बाद ही सार्वजनिक होगा समझौता- ट्रंप

वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते का पूरा हिस्सा शुक्रवार को औपचारिक हस्ताक्षर के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उपराष्ट्रपति वेंस हस्ताक्षर समारोह में शामिल होंगे, जबकि उनकी अपनी उपस्थिति अभी तय नहीं है।

*19 जून को जिनेवा में लगेगी

ट्रंप ने इस समझौते को क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने वाला महान समझौता बताया है। उनका दावा है कि इसके लागू होने के बाद क्षेत्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बड़ा लाभ मिलेगा तथा लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी।

ट्रंप ने ये भी कहा कि शुक्रवार तक होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खुल जाएगा।

ट्रंप बोले- ईरान से समझौता साइन हो चुका- शुक्रवार तक होर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा, दोबारा हमला करना पड़ा, इसका दुख है

क्या है समझौते का मुख्य उद्देश्य?

फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बात करते हुए ट्रंप ने कहा, डील पर पूरी तरह से साइन हो गए हैं और जलडमरूमध्य आंशिक रूप से खुल भी गया है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से अहम यह जलमार्ग शुक्रवार तक पूरी तरह से खुल जाएगा, जो ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी सप्लाई को बहाल करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। इस प्रारंभिक समझौते का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में लागू नाजुक युद्धविराम को मजबूत करना और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने का रास्ता तैयार करना है। यह समुद्री मार्ग दुनिया में तेल और गैस आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है। हालांकि, जलडमरूमध्य को समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने के बाद ही खोला जाएगा।

> **ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पहले से ही कुछ-कुछ खुला है और यह शुक्रवार को पूरी तरह खुल जाएगा. जी7 समिट में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के साथ मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा, वे कुछ माइंस की थोड़ी खोजबीन कर रहे हैं जो उन्हें पहले ही मिल चुकी हैं, लेकिन अब जहाज निकलने लगे हैं. शुक्रवार को, यह पूरी तरह खुल जाएगा.**

अमेरिका-ईरान के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी- अराघची

वहीं, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि शुक्रवार के समारोह के बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों और अमेरिका द्वारा कथित रूप से किए गए वादाखिलाफी को देखते हुए ईरान बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान इस समझौते के जरिए देश के लिए अधिकतम आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा।

शांति समझौते के सामने हैं कई बड़ी चुनौतियां

हालांकि, समझौते के सामने कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, इस्राइल और हिजबुल्ला के बीच जारी तनाव तथा लेबनान से जुड़े मुद्दे अभी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। ईरान लगातार कहता रहा है कि लेबनान से जुड़े मुद्दों को अंतिम समझौते का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उधर, इस्राइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर ने कहा कि ट्रंप और ईरान के बीच हुआ समझौता इस्राइल पर बाध्यकारी नहीं है।